(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे नियम बनाने का है जिसके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की एक पृथक वरीयता सूची रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) गृह मंत्रालय के दिनांक 11 जुलाई, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-12-67-स्थापना (ग) के आदेशों में पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने की कार्यविधि विस्तृत रूप से दी गई है। श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV के आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पृथक प्रवर-सूचियां बनानी होती है। उपरोक्त आदेशों में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की श्रेणी-III से श्रेणी-II में पदोन्नति, श्रेणी-II के भीतर पदोन्नति, तथा श्रेणी-II से श्रेणी-I के प्रथम चरण में पदोन्नति, जिनमें पदोन्नति के लिए आरक्षणों की व्यवस्था नहीं है, की कार्यविधि भी विस्तार से दी गई है। यह कार्यविधि सन्तोषप्रद ढंग से चल रही है। इसलिए यह आवश्यक नहीं जान पड़ता कि दिनांक 11 जुलाई, 1968 के आदेशों को संशोधित किया जाए या ऐसे नियम बनाए जाएं जिनके अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियो की एक पृथक वरीयता सूची रखी जाए।

CENTRAL GOVERNMENT'S DIRECTIVE TO GOVERNMENT OF ORISSA TO TREAT RESERVED VACANCY AS UNRESERVED WITHOUT CENTRE'S CONCURRENCE

5723. SHRI GAJADHAR MAJHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government of India have issud any order to the Government of Orissa that reserved vacancy for Scheduled Caste and Tribe can be declared as unreserved without prior concurrence of the Central Government;

(b) whether the Government of Orissa is following the same; and

(c) if not, the reason therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) No, Sir. The reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services under the State Governments are the concern of the respective State Governments under Article 335 read with Articles 16(4) and 12 of the Constitution. Hence, no orders in this regard can be issued by the Government of India to the State Governments.

(b) and (c). Do not arise.

DELHI-RANCHI STD SYSTEM

5724. KUMARI KAMLA KUMARI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government propose to start Subscribers Trunk Dialing for Ranchi (Bihar) from Delhi; and

(b) if so, the main features thereof and the time by which it would be started?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N.B AHUGUNA): (a) Not at present.

(b) the Present trunk traffic between Delhi and Ranchi is not sufficiently high to justify a point-to-point Subscriber Trunk Dialling routs. The routes having higher traffic are being taken up first. The Ranchi-Delhi route is expected to be put under STD by the end of the Fifth Plan period.

JURISDICTION OF C.B.I. AND OF VIGILANCE COMMISSION

5726. SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: